THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) Sir, as sales tax is a State subject, it is for the States to take a decision in this regard.

(e) and (d) There is a proposal for reduction in rates of Central Sales Tax in a phased manner. A Committee of six Chief Ministers has been set up to look into the matter and make suitable recommendations.

Rise in the value of Hard Currency

2530. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the exporters are discouraged due to rise in the value of hard currency as a result of which the export of the country has declined; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) Export performance is influenced by a variety of (actors-domestic as well as external, besides exchange rate movements. Increase in the value of hard currencies vis-a-vis the domestic currency is expected to increase the price competitiveness as well as profitability of domestic exports.

Under the current exchange rate mechanism, the external value of the Indian rupee is market determined. The Reserve Bank of India keeps a close watch on the exchange rate movements in order to ensure orderly conduct in the foreign exchange markets in India.

मुम्बई शेयर बाजार में शेयरों का हेर-फेर

2531. **श्री गुरूदास दासगुप्त**:
श्री जे. चितरंजन:
श्री जनेश्वर मिश्र:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में मुम्बई शेयर बाजार में शेयरों के हेर-फेर में प्रतिभूति घोटाले के एक प्रमुख दोषी की अंतर्ग्रस्तता के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा की गई जांच की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में कुछ स्क्रिपों में कीमत संबंधी कथित छल-कपट की जांच-पड़ताल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की गई थी। जांच-पड़ताल में प्रथमदृष्टया यह पता चला कि ग्राहकों के एक सामान्य दल, जिसमें मुख्यतः सात कंपनियां शामिल है , की ओर से, उनकी सहमति से कार्य कर रहे ब्रोकरों के एक दल ने बी. एस. ई. और एन. एस. ई., दोनों में इन शेयरों का काफी बड़ा हिसा समेट लिया है तथा प्रतीत होता है कि उन्होंने इन स्क्रिपों की कीमतों में हेर-फेर किया है। जांच-पड़ताल से आगे यह पता चला कि 1992 के प्रतिभूति घोटाले के एक अधिसूचित व्यक्तिम हर्षद मेहता के साथ इन कंपनियों के निकट संबंध थे और वे उसके लिए एक मोर्चे के रूप में कार्य कर रहे थे।

Strike by officials of central excise, customs and income-tax

2532. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE pleased to state:

(a) whether the officials of the Central Excise, Customs and Income Tax recently went on strike paralysing the international airports, major and minor ports and cargo complexes;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) what are the reasons for resorting to strike by these officials stating the extent of loss suffered by Government as a consequence thereof; and

(d) the steps taken by Government to resolve the issues involved?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) and (b) Sir, Groups 'B* and *C officers of the Central Excise, Customs and Income Tax were on strike from 10th November, 1998 to 12th November, 1998. But international air-ports, major and minor ports and cargo complexes were not paralysed.

(c) The employees were demanding higher pay scales and improvement in some of the service conditions. The strike did not lead to any loss, of revenue.

(d) The demands are being examined.

IDBI's tie up with us based principal financial group

2533. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:

SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Industrial Development Bank of India (IDBI) is considering a proposal to tie up with the US based Principal Financial Group for management of Provident and Pension Funds in the country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHA-NAN): (a) and (b) Industrial Development Bank of India (IDBI) has reported that Principal Financial Group, a leading provider of pension products based in the United States has held preliminary discussions with IOSI Capital Market Services Ltd., a subsidiary of IDBI to Explore the possibility of a tie up for management of provident and pension funds in India.

न्यु इंडिया एश्योरेंस कम्पनी की स्वायत्तता

2543. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी के आधिकारियों ने साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) से स्वायत्तता की मांग की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन्होने आरोप लगाया है कि साधारण बीमा निगम (जी. आई. सी.) के नियंत्रण में कार्य करते हुए इनकी कम्पनी को घाटा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उक्त मांग पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत में बीमा क्षेत्र में प्रीमियम की राशि बहुत कम है; और

(ड) यदि हां, तो सरकार भारत में बीमा प्रीमियम कि राशि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व और बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम. आर. जनार्दन): (क) जी, हां। यह सूचित किया गया है कि अधिकारी संघ ने कलकत्ता में हाल में सम्पन्न विचारगोष्ठी में कम्पनी को स्वायत्ता प्रदान करने सम्बन्धी मांग को सामने रखा था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। न्यू इंडिया द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह गलत है और इस बयान का कोई आधार नहीं है।

(घ) और (ड) देश में व्याप्त संभाव्यता की तुलना में साधारण बीमा क्षेत्र में प्रीमियम की राशि कम है। देश में बीमा प्रीमियम कि राशि मे वृद्धि करने के लिए लोगों के मध्य जागरूकता बढ़ाने,बीमा प्रभाव बढ़ाने, बोर्ड द्वारा कार्यनिष्पादन की समीक्षा, उत्पादों के नई तरीकों, नयी सूचना प्रोद्योगिकियों को अपनाने आदि जैसे कई उपाय किए जा रहे है।

नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को लोकल एरिया बैंक खोलने की अनुमति

2535. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पी. एच. डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने यह अनुरोध किया है कि "ए" क्रेडित रेटिंग से सम्पन्न नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को लोकल एरिया बैंक खोलने के अनुमति मिलनी चाहिए;